







# सम्पादकीय अनुचित और अमर्यादित

कुछ समय पहले तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणियों की चर्चा होती रही है। कहा गया कि इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव सार्वजनिक हुआ है। चर्चा रही कि इससे जनमानस में अविश्वास व भ्रम की स्थिति बनती है। अब इस टिप्पणी से उत्साहित होकर भाजपा के दो सांसदों ने लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ पर अमर्यादित ढंग से निशाना साधा है। उस महत्वपूर्ण स्तंभ पर जिसका कार्य संविधान की गिरिमा बनाना और न्याय सुनिश्चित करना है। दरअसल, विधानसभाओं में विधेयकों को मंजूरी देने के लिये समय सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि 'कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं।' वहीं दूसरी ओर लोकसभा में झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने भी चिंताजनक ढंग से तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का काम अपने हाथ में ले ले तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को भी नहीं बच्चा और उन्हें देश को गृह युद्ध की ओर धकेलने वाला बताया। इतना ही नहीं, कुछ समय उपरांत उन्होंने अपने बयान को और हल्का करते हुए कहा कि एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त 'मुस्लिम आयुक्त' की भूमिका में रहे हैं। बहुत संभव है कि दोनों भाजपा नेताओं ने पार्टी में अपना कद बढ़ाने के मकसद से ऐसे बयान दिए होंगे। यह भी कि उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को बढ़ा करके दिखाने का ही प्रयास किया। उन्हें लगता है कि शायद पार्टी उन्हें उनकी वपफदारी के लिये पुरस्कृत करेगी। लेकिन भागवा पार्टी ने उन्हें सिर्फफटकर ही लगाई है। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने खुद को उनकी व्यक्तिगत टिप्पणियों से अलग रखने की बात कही है। निस्संदेह भाजपा को लोकतंत्र के अभिन्न अंग के रूप में न्यायपालिका के प्रति अपने सम्मान की भी पुष्टि करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि जब तक दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक भाजपा का यह दावा अविश्वसनीय ही बना रहेगा। पहले भी भाजपा के शीर्ष नेताओं ने तब भी उस बयानबाजी को प्रत्रय नहीं दिया, जब आक्रामक बयानबाजी करने वाली सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अनर्गत बयानबाजी की थी। उल्लेखनीय है कि प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहकर हंगामा कर दिया था। तब भी पार्टी ने बस इतना किया था कि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था और संसदीय पैनल से हटा दिया था। तब उन्होंने दो बार लोकसभा में मापे भी मांगी थी। कालांतर समय के साथ मामला शांत हो गया था। जैसा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को उम्मीद भी थी। लेकिन इस बार भी यदि ऐसा ही नतीजा सामने आता है तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। यह देखते हुए कि दुबे और शर्मा ने मर्यादा की एक सीमा रेखा को पार किया है, वह स्पष्ट रूप से न्यायालय और संविधान की अवमानना के दायरे में है। जिसके लिये उन्हें क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, ऐसे अप्रिय विवादों से जनता में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव का नकारात्मक संदेश जाता है। जिससे अनावश्यक संवैधानिक संकट की स्थिति भी बन सकती है। जनता में लोकतंत्र के आधारभूत संभों को लेकर अविश्वास का भाव पैदा नहीं होना

देना चाहिए। दरअसल, ऐसे अनावश्यक विवादों से किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। बल्कि तत्ख्य बयानबाजी से बेकार की बहस बढ़ने की आशंका ही बलवती होती है। खासकर संविधानिक पदों पर बैठे लोगों के तो ऐसी बयानबाजी से परेज करना ही चाहिए। दरअसल, संविधान ने न्यायपालिका को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं कि जब पूर्ण न्याय के लिये कोई अन्य रास्ता नहीं बचता, तब वह विशिष्ट अनुच्छेदों से मिली शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। दूसरे शब्दों में इसे उम्मीद के एक दरवाजे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

## सीपीआई(एम) जनता के बीच जायेगी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की 24वीं कांग्रेस 6 अप्रैल को मदुरै में संपन्न हुई। कांग्रेस में स्वीकृत राजनैतिक प्रस्ताव में भाजपा-आरएसएस को अलग-थलग करने और उसे हराने का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किया गया है। यह प्रस्ताव सही ढंग से इसका विश्लेषण करता है कि मोदी सरकार के लगभग 11 वर्षों के शासन में नव-फसीवादी विशेषताओं वाली दक्षिणपंथी, सांप्रदायिक, तानाशाही ताकतें मजबूत हुई हैं। यह प्रस्ताव रेखांकित करता है कि मोदी सरकार हिंदुत्ववादी ताकतों और बड़े पूँजीपतियों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, मुख्य कार्य भाजपा-आरएसएस और इसके पीछे की ताकत हिंदुत्व-कॉर्पोरेट गठजोड़ से लड़ा और उसे हराना है। इस राजनैतिक प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि सांप्रदायिक ताकतों की विचारधारा और गतिविधियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करके ही भाजपा और हिंदुत्ववादी ताकतों को अलग-थलग करना और हराना संभव है। हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता के खिलाफ सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की व्यापक लामबंदी के लिए प्रयास करते हुए भी, सीपीआई(एम) इस बारे में स्पष्ट है कि हिंदुत्ववादी नवउदारवादी शासन के खिलाफ संघर्षों की सफलता के लिए सीपीआई(एम) और वामपंथी ताकतों की स्वतंत्र ताकत का विकास जरूरी है। पार्टी और वामपंथ की स्वतंत्र ताकत और प्रभाव में ढहराव - और बाद में गिरावट - काफी समय से चिंता का विषय रहा है। पार्टी को अपने पूर्व गढ़ पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भारी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप उसका जनाधार कम हो गया है। इस संबंध में, राजनीतिक समीक्षा रिपोर्ट में यह उल्लेख करते हुए कि पार्टी भाजपा के विरुद्ध व्यापक धर्मनिरपेक्ष ताकतों को संगठित करने में सफल रही, आत्मालोचनात्मक रूप से यह भी स्वीकार किया गया है कि वह 23वीं कांग्रेस द्वारा निर्धारित अन्य कार्यभार को पूरा करने में विफल रही रू अर्थात् इसके साथ ही, माकपा और वामपंथ की ताकत और प्रभाव को बढ़ाना। 23वीं कांग्रेस में स्वीकृत राजनैतिक-रणनीतिक लाइन को सही बताते हुए 24वीं कांग्रेस ने हिंदुत्व और विभिन्न आरएसएस संगठनों के प्रभाव और गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर गतिविधियों का संचालन करने के लिए पार्टी को तैयार करने का आद्वान किया है। यह प्रस्ताव दोहराता है कि भाजपा और आरएसएस को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है और उन्हें केवल चुनावी लड़ाइयां के जरिए नहीं हराया जा सकता है। यह देखते हुए कि पिछले दशक में हिंदुत्ववादी ताकतों ने वैचारिक प्रभाव के आधार पर एक बड़ा समर्थन आधार बनाया है, उनका मुकाबला करने के लिए एक सर्वसमावेशी कार्यक्रम का होना आवश्यक है। इस दिशा में पार्टी मजदूर वर्ग के बीच और मजदूर वर्ग के रिहायशी इलाकों, ट्रेड यूनियनों और अन्य जन संगठनों और मंचों पर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए सांप्रदायिकता विरोधी कामों को संगठित करने पर विशेष ध्यान देगी। अन्य उपायों के अलावा, पार्टी धार्मिक आस्था और राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के दुरुपयोग के बीच अंतर समझाने के लिए आस्थावानों तक पहुँचेगी।

RNI NO. : DELHIN/2022/86048

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक मो. अकिलुर रहमान द्वारा  
आर.डी. प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड नोएडा से  
मुद्रित व जे-29, जे-एक्स्स. गली नं-9, लक्ष्मी नगर, दिल्ली  
110092 से प्रकाशित। सभी प्रकार के विवादित मामलों का

निपटारा दिल्ली के न्याय क्षेत्र में ही होगा।  
सम्पादक : मो. अकिलुर रहमान  
Email : [rajinitaldeep@gmail.com](mailto:rajinitaldeep@gmail.com)

Email : rajnitikdaon@gmail.com  
Meh : 0560268603

Mob : 9560268603

राजेंद्र शम

फासीवादियों की एक जाने-मानी रणनीति है। खुद करना चाहते हों, करने जा रहे हों, विरोधी पर बढ़ाने का आरोप लगा दो। भाजपा के बदजुबान मोदी जी निजाम के मुहल्ले सांसद, निश्चिकातं दुबे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना पर शदेश में



नीति गठजोड़ सरकार ने तमिलनाडु की आशंकाओं को ही सच साबित करते हुए, इसका ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत, त्रिभाषा पफूले की तीसरी भाषा के रूप में महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य की जा रही है। हैरानी की बात नहीं है कि इस निर्णय का व्यापक रूप से विरोध भी हो रहा है। बहरहाल, इसके सामानंतर मुंबई के कुछ हिस्सों से एक बार फिर गुजरातियों और मराठियों के बीच तनाव बढ़ने की खबरें आने लगी हैं। यह भी याद रहे कि तमिलनाडु बनाम राज्यपाल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमले की शुरूआत, निशिकांत दुबे से दो-तीन दिन पहले, भारत के उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर चुके थे। धनखड़ जो सर्वोच्च न्यायालय के तथाकर्थित अतिक्रमणों से संसद की ओर वास्तव में कार्यपालिका की हिफजत करने के नाम पर पहले भी कई बार तलवार भांज चुके हैं, इस बार सर्वोच्च न्यायालय से इस बात से खफ थे कि उसने राज्यपालों द्वारा और यहां तक कि राष्ट्रपति द्वारा भी, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर मंजूरी या नामंजूरी का निर्णय करने के लिए, तीन महीने की अधिकतम सीमा तय कर दी है। उनके अनुसार यह राष्ट्रपति की ओर उसकी नियुक्तियों के रूप में राज्यपालों को भी सर्वोच्चता का अतिक्रमण है! अदालत राष्ट्रपति को कुछ भी निर्देश कैसे दे सकती है, भले ही यह इसी का निर्देश क्यों न हो कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर बैठे ही नहीं रहें, तीन महीने के अंदर उन पर अपना कोई न कोई फैसला दे दें! सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने में समर्थ बनाने वाली संविधान की धारा-142 को तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने रेजन्टनाट्रिक ताकतों के खिलाफ नाभिकीय मिसाइल, जो न्यायपालिका को 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध हैशृं ही करार दे दिया। यह इसके बावजूद था कि बाबरी मस्जिद बनाम रामजन्म भूमि विवाद में, मर्दिर

के पक्ष में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने काथित रूप से शश्वर्ण न्यायशः करने के लिए ठीक इसी धारा का सहारा लिया था। पिछे भी यह अकारण ही नहीं है कि धनखड़ से भिन्न, निशिकांत दुबे तथा दिनेश शर्मा जैसे भाजपायी सांसदों ने, आम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय पर और खासतौर पर मुख्य न्यायाधीश पर निशाना साधते हुए, वक्फ बोर्ड के मुद्रे को ही सबसे आगे रखा है। इसका सीधा संबंध, वक्फ कानून में संशोधनों के हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक मंतव्यों से है। बेशक, संघ-भाजपा की ओर से इसका काफी स्वांग भी किया जाता रहा है और जाहिर है कि इसमें संसद में बहस के दौरान तथा उसके बाद के भी उनके जुबानी दावे भी शामिल हैं, कि ये संशोधन वास्तव में मुसलमानों को लाभ पहुंचाने की चिंता से किए जा रहे हैं। कि इन संशोधनों से विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं व परमांदा मुसलमानों को और मुसलमानों के बोहरा आदि कमजोर पंथों को पर्यटदा मिलने वाला है। कि इसका हिंदुओं के तुष्टिकरण से कोई संबंध नहीं है, आदि। इसके बावजूद, इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की असली नीयत तब खुलकर सामने आ गयी जब रातों-रात संघ-भाजपा के युवा संगठनों ने विभिन्न राज्यों को ऐसे पोस्टरों से पाप दिया, जो वक्फसंशोधन विधेयकों का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों को, हिंदू-विरोधी घोषित करते थे। यह इसका खुला ऐलान था कि यह कानून, सबसे बढ़कर हिंदू सांप्रदायिकता के आग्रहों से ही सचालित है। एक प्रकार से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्फ अधिनियम के खिलाफ चुनौतियों की सुनवाई पर अपनी शुरूआती प्रतिक्रिया में बिना कहे इस सच्चाई को स्वीकार भी किया है। इसीलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के कम से कम तीन पहलुओं पर फैरी तौर पर रोक लगाने की जो मंशा जातायी थी, उसके बाद मोदी सरकार ने अपनी ओर से ही संबंधित पहलुओं का परिचालन अगले अदालती आदेश तक रोके रखने का आश्वासन दे दिया। अदालत ने इस आश्वासन को आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया और इस तरह वक्फ अधिनियम के अमल को ही अदालत द्वारा रोके जाने की शर्मिंदगी से तो सरकार बच गयी, लेकिन इन कदमों को अपनी ओर से ही रोके रखने का वादा करने के बाद ही। इस तरह जिन दो सबसे समस्यापूर्ण पहलुओं का अमल रोक दिया गया, उनमें एक तो वक्फबोर्ड तथा वक्फकार्डिल का राज्यों के स्तर तक पुनर्गठन ही है। इस सिलसिले में विवाद तथा अदालती चुनौती के केंद्र में अधिनियम का यह प्रावधान है कि अब तक के कायदे के विपरीत, उक्त निकायों में गैर-मुसलमानों को भी रखा जा सकता है। शिकायत यह है कि नये प्रावधानों के तहत बोर्ड और कार्डिल में गैर-मुस्लिमों का बहुमत तक हो सकता है। इस संदर्भ में इस कानून का विरोध करने वालों का तर्क यह है कि यह तो अपनी धार्मिक संस्थाओं का स्वतरु रूप से संचालन करने की, देश के संविधान में सभी समुदायों को दी गयी स्वतंत्रता का ही उल्लंघन है। इसके अलावा इस प्रबल तर्क का भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था कि क्या वह अन्य धर्मों पर व संप्रदायों की संस्थाओं में भी इसी प्रकार, अन्य धर्मवर्लांबियों को जगह देने जा रही है? पिलहाल स्थगित कर दिया गया दूसरा ऐसा ही समस्यापूर्ण पहलू वक्फ बाई यूज यानी वक्फ के रूप में उपयोग होते आने से किसी संपत्ति की वक्फ के रूप में मान्यता का है। नया कानून वक्फ बाई यूज को अमान्य करता है और इस प्रकार सैकड़ों साल पुरानी अनेक मस्जिदों, कब्रिस्तानों, खानकाहों आदि पर संपत्ति विवादों का रास्ता खोलता है। मुद्दा यह है कि वर्तमान संपत्ति रजिस्ट्रेशन कानूनों के अमल में आने से पहले से वक्फ के रूप में चली आ रही संपत्तियों के मामले में, रजिस्ट्रेशन आदि के कागजात कहां से आएंगे और किस के पास मिलेंगे? इस तरह नये कानून के बनते ही, अनेक पुरानी संपत्तियों पर विवाद खड़े हो जाने का गस्ता रोक दिया गया है। बेशक, नये कानून को चुनौती दिए जाने के प्रमुख मुद्रे और भी हैं, जिन पर पिलहाल पाबंदी लगाना जरूरी नहीं समझा गया है। इनमें बुनियादी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला यह प्रावधान भी शामिल है कि वक्फकरने के लिए, संबंधित शाष्कश का पांच साल से धर्मपालक मुसलमान रहा होना जरूरी है। इसी प्रकार, एक और महत्वपूर्ण मुद्रा नये कानून में जिलाधीश को वक्फसंपत्तियों के दर्जे के संबंध में निर्णय के तमाम अधिकार सौंपे जाने से लेकर, किसी संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा किए जाने की सूरत में, जिलाधीश द्वारा अंतिम निर्णय किए जाने तक, उसका वक्फसंपत्ति का दर्जा ही स्थगित हो जाने तक जाता है। बहरहाल, पिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने हस्तक्षेप से नये कानून के सबसे आपत्तिजनक तथा समस्यापूर्ण प्रावधानों का अमल स्थगित करा दिया है और अदालत ने एक हद तक अपने सोच की दिशा का भी इशारा कर दिया है। यही सुप्रीम कोर्ट पर संघ-भाजपा के इस बौखलाहट भरे हमले का मुख्य कारण है।

# सर्वोच्च न्यायालय का वकफ कानून पर सबको खुश करने वाला अंतिम आदेश

ਪੰਜਾਬ

विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोन्मत्ता न्यायालय के अंतरिम आदेश ने विरोधी ओरों के बीच एक असामान्य संतुलन पैदा कर दिया है, जो निर्णायक हस्तक्षेप के बजाय एक सुनियोजित संतुलनकारी कानून का संकेत देता है। हालांकि यह आदेश संशोधनों का कार्यान्वयन पर पूर्ण रोक का प्रतिनिधित्व नहीं करता लेकिन यह न्यायिक संघरण की एक प्रति प्रतिक्रिया करता जो आश्वस्त और अस्थिर दोनों है, जो इस बात पर नियंत्रण करता है कि व्यक्ति किस पक्ष में है। यह कानूनी युद्ध मैदान को खुला छोड़ देता है, लेकिन संकेत- हालांकि कमजोर- सरकार की स्थिति के अंतिम समेकन व और इशारा करते हैं सरकार को यथास्थिति बनाये रख हुए अधिक मजबूत तर्क प्रस्तुत करने का समय देकर न्यायालय ने अधिक गहन जांच के लिए मंच तैयार किया है जो अंतररूप विचाराधीन संशोधनों को वैध बना सकता है। सरकार के दृष्टिकोण से, यह अंतरिम व्यवस्था न केवल स्वीकार्य है- परन्तु उसके लिए लाभप्रद भी है। यह मौजूदा कानूनी ढांचे में ठोस खामियों को प्रदर्शित करके बहस को सैद्धांतिक से अनुभवजन्य में बदलने व अनुमति देता है। पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति के रूप नामित किये जाने की रिपोर्ट, अक्सर निवासियों व जानकारी या सहमति के बिना, निराशा की एक लंग पैदा करती है जिसे सरकार न्यायालय के समक्ष बढ़ावा चाहती है। इस मुद्दे को सामूहिक वर्चितता और प्रणालीय अस्पष्टता के रूप में प्रस्तुत करके, सरकार न केवल प्रशासनिक आवश्यकता, बल्कि सामाजिक न्याय का कहानी गढ़ रही है। पिछे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस

कहानी एक ऐसी अदालत के साथ प्रतिध्वनित होने की संभावना है जिसने पिछले फैसलों में कानून की सिद्धांतवादी व्याख्याओं पर संतुलन और व्यावहारिकता की ओर झुकाव दिखाया है। समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि न्यायालय ने संशोधित कानून के संचालन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन मुकदमे के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति में इस तरह से बदलाव न करने की चेतावनी दी, जिससे किसी भी पक्ष के अधिकारों को नुकसान पहुँचे। यह दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। ये कानूनी चुनौती को निरर्थक बना सकते हैं। लेकिन सरकार के लिए, यह अभी भी अपना मामला बनाने, डेटा एकत्र करने और पिछली व्यवस्था के तहत लंबे समय से चले आ रहे अन्याय के लिए आवश्यक सुधार के रूप में संशोधन को तैयार करने का गस्ता खुला छोड़ता है। न्यायालय के निर्देश के शब्द ही कठोर अंतरिम कदम उठाने की अनिच्छा को दर्शाते हैं, जो अंतिम फैसले के समय उसके हाथ बांध सकते हैं। इस स्थिति से जो उभरता है, वह एक तरह की न्यायिक हेंजिंग है—चुनौती देने वालों को उम्मीद देने के लिए पर्याप्त अस्पष्टता, लेकिन सरकार के लिए पैंतेरेबाजी करने के लिए पर्याप्त जगह। चुनौती देने वालों को निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा की गयी कुछ टिप्पणियों से सांत्वना मिली है, जो संशोधनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के अधिकारों के लिए कुछ हद तक सहानुभूति का संकेत देती है। लेकिन यह सांत्वना अंतर्रूप वास्तविक से ज्यादा बयानबाजी साबित हो सकती है। न्यायालय का इतिहास बताता है कि जब तक विचाराधीन कानून स्पष्ट रूप से असरवैधानिक या घोर अन्यायपूर्ण न हो, तब तक यह विधायी और कार्यकारी शाखाओं के अधीन रहता है, खासकर जब व्यापक शासन संबंधी मई शामिल

हों क्रिश्चियन एलायंस और एसोसिएशन ऑफ सोशल एक्शन जैसे नये हस्तक्षेपकर्ताओं के साथ सरकार का रणनीतिक गठबूधन इसके हाथ को और मजबूत करता है। इन समूहों का तर्क है कि पिछले कानून को धार्मिक या संस्थागत दावों के तहत व्यक्तियों- अक्सर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से- को उनके वैध संपत्ति अधिकारों से बचना करने के लिए हथियार बनाया गया था। ऐसी आवाजों को एकजुट करके, सरकार कानून को बहुसंख्यकवादी थोपे जाने के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी सुधार के रूप में फिर से परिभाषित कर रही है। यह पुनर्स्थापन महत्वपूर्ण है। यह मुद्दे को एक संकीर्ण प्रश्नासनिक बदलाव से संपत्ति के अधिकारों को बहाल करने और ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करने के लिए एक नैतिक धर्मयुद्ध में बदल देता है। न्यायपालिका, जब इस तरह के नैतिक ढांचे का सामना करती है- खासकर अगर वास्तविक जीवन की गवाही और आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है- अक्सर विधायी इरादे को बनाये रखने की ओर झुक जाती है जब तक कि एक मजबूत संवैधानिक उल्लंघन साबित न हो जाये। नये कानून के तहत प्रक्रियात्मक चिंताएं या कथित अतिक्रमण के उदाहरण भी इसे अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं जब तक कि मनमानी या लक्षित भेदभाव का एक स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखाया जा सकता है। अब तक, चुनौती देने वालों ने वास्तविक नुकसान के प्रलेखित मामलों के बजाय संभावित दुरुपयोग के जोखिम पर अधिक ध्यान दिया है। इसके विपरीत, सरकार मौजूदा प्रणाली की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो पहले से ही मूर्त और प्रदर्शन योग्य हैं। साक्ष्य की गुणवत्ता और प्रकृति में यह विषमता अंतिम निर्णय में भारी पड़ सकती है। इसके अलावा अदालत की अंतरिम टिप्पणियों की भाषा संभावित जटिलताओं के बारे में गहरी जागरूकता का सुझाव देती है जो विधायी प्रक्रिया में समय से पहले हस्तक्षेप करने से उत्पन्न हो सकती है। इस बात पर जोर देकर कि मामले के लंबित रहने के दौरान कोई नयी जटिलताएं पेश नहीं की जानी चाहिए, अदालत समय खरीदती हुई प्रतीत होती है - न कि समय पर निर्णय लेने के लिए कानून के बारे में बात करना और बिना व्यवधान पैदा किए निष्पक्ष सुनवाई करना। यह सतर्क दृष्टिकोण, तटस्थ प्रतीत होते हुए भी, अक्सर यथास्थिति या इस मामले में, नये पेश किये गये परिवर्तनों के पक्ष में काम करता है। एक बार जब कोई कानून व्यवस्था में स्थापित हो जाता है - यहां तक कि एक अंतिम क्षमता में भी- तो इसे उलटना संस्थागत रूप से अधिक कठिन हो जाता है जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई भारी कारण न हो। इसके अतिरिक्त, संशोधनों का समर्थन करने वाली आवाजों की बढ़ती संख्या से न्यायालय के प्रभावित होने की संभावना है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों और सामाजिक वकालत समूहों से। ये हितधारक अपने साथ एक हृद तक नैतिक और सामाजिक-राजनीतिक वैधता लाते हैं जिसे नजरदाज करना मुश्किल है। कानूनों के पिछले शासन के तहत बहिष्कार और बेदखली के उके आख्यान एक भावनात्मक और मानवीय आयाम पेश करते हैं जो अन्यथा एक अमूर्त कानूनी प्रतियोगिता हो सकती है। यदि चुनौती देने वाले तुलनात्मक रूप से सम्पोहक प्रति-कथा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं - जो कानूनी तकनीकों से पेर हो और न्याय को एक अंतरिक तरीके से संबोधित करे-तो पेंडुलम सरकार के पक्ष में ज़िलता रहेगा।

# राहुल ने खोली चुनाव आयोग की पोल



वोटिंग की। चुनाव आयोग द्वारा शाम 5.30 बजे तक मतदान के आंकड़े जारी किये गये थे। बाद में जो अंतिम आंकड़े प्रदान किये गये उसके अनुसार शाम 5.30 बजे से 7.30 बजे के बीच 65 लाख लोगों ने मतदान किया। ऐसा होना संभव ही नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। इस हिसाब से तो सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की कतरें लगनी चाहिये थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कांग्रेस व विपक्ष ने आयोग से वीडियो सबूत मांगे तो उसे न केवल मना कर दिया गया बल्कि आयोग ने कानून ही बदल दिया ताकि विपक्षी दल वीडियोग्राफी

के लिए न कह सकें। गौरतलब है कि राहुल ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ऐसे बहर में चुनावी गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है जब कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके खासमखास दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने साफ किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। बैलेट पेपर की हिमायत करते हुए मस्क ने तो यहां तक कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। यानी वे उस आरोप की पुष्टि कर रहे हैं जो भारत के कई विपक्षी दल 2022 से लगा रहे हैं। आरोप है कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में वोटिंग मशीनों में बढ़े पैमाने पर धांधली कर भाजपा ने दो-चार नहीं वरन् लगभग 80 सीटें जीती हैं। इतना ही नहीं, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी एक खास पैटर्न के द्वारा हारती हुई भाजपा ने चंद घंटों में इतनी सीटें जीत लीं कि वह सरकार बनाने में कामयाब हो गयी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उदाहरण इस सिलसिले में दिये जाते हैं। वैसे तो भारत में जिस तरह से शासकीय मशीनी के जरिये लोकतंत्र को अपहृत किया गया है और मोदी सरकार निरंकुश तरीके से काम कर रही है, वह दुनिया अब जान चुकी है, राहुल द्वारा जो बातें भारतीय समुदायों के समक्ष कही जा रही हैं, वह दूर तक जायेगी क्योंकि वहां का मीडिया एक तरह से वैश्विक कहा जाता है जो निश्चित ही भारतीय मीडिया के मुकाबले बहुत अधिक जननांत्रिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भारत का मीडिया विषय की बातों को जहां स्थान नहीं देता वहां अमेरिकी या लोकतंत्रिक रूप से परिपक्व किसी भी देश का मीडिया सरकार की बजाय प्रतिपक्ष को तरजीह देता है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की बातें एक बार पिर से विश्वपटल पर प्रमुखता से लोगों के सामने आयेगी। अनुमानों के मुताबिक भाजपा ने राहुल के इस बयान को संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया तथा राहुल पर देश को बदनाम करने की सुपारी लेने का आरोप लगा दिया है। पार्टी के प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि, राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। यही उनकी पहचान बन गई है। यह दिखाता है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करते हुए भारत के विरोध पर उत्तर गये हैं— वह भी विदेशी धरती पर। पूनावाला के अनुसार पूरी दुनिया भारत के चुनाव आयोग और निर्वाचन प्रणाली की प्रशंसा कर रही है पर भारत के खिलाफ और देश की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम कर रहा है।







# सोशल मीडिया प्रेशर पर बनेगी फिल्म, डिप्रेशन के चलते थैरेपी ले रहे सितारे

अभिनेत्री नुसरत भरुचा छोरी 2 को लेकर वर्च में बढ़ी है और उन्होंने संवाद कार्यक्रम में अपनी फिल्म के साथ-साथ गंभीरता से किरदार निभाने के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने बताया कि वह सोशल मीडिया पर ही ट्रोलिंग से कैसे निपटी है।

छोरी 2 के दौरान आई ये चुनौतियां दरअसल, छोरी 2 में अपने किरदार को निभाने के लिए नुसरत को जुड़े मुश्किल दौर से जुरूरना पड़ा। उन्होंने उन चुनौतियों के बारे में भी बात की। किरदार को निभाने की तुलनियों के बारे में बात करते हुए नुसरत ने कहा कि छोरी और छोरी 2 में जो सबसे मुश्किल काम था, वो यह एक मां का किरदार निभाना, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में जो अनुभव किए हैं, उसे मैं पर्दे पर आसानी से निभा सकती हूं।

पर्दे पर मां बनना बहुत मुश्किल था। मैं जब छोरी 2 देखती हूं तो यह देखती हूं कि क्या मैंने मां को इमानूल को ठीक से किया है। मेरे लिए वह फिल्म बहुत जरूरी थी, इसलिए दोनों फिल्मों में वह मेहनत मेरे लिए बहुत जरूरी थी।

**एक्टर्स को थैरेपी**  
लेना बहुत जरूरी  
नुसरत ने किरदारों से बाहर निकलने के बारे में बात करते हुए कहा कि छोरी और छोरी 2 के लिए वह मुझे और विशाल सर को काफी चर्चा करनी पड़ी। मेरी बच्ची मुझसे इन गिरहे हैं, उस इमानूल में मुझे लगातार रहना पड़ा। परी शृंग के दौरान। एक ऐसी फिल्म में घुसना और निकलना बाकर्क बहुत मुश्किल है। हम एक्टर्स को बाकर्क एक फिल्म के बाद थैरेपी लेनी चाहें कि इन इमानूल से

लगातार रहना हो। अब हम इस पर काम भी किया जा रहा है। अब इस पर काम भी किया जा रहा है।

**जनरल के फैंस के लिए खुशखबरी**  
मैं फिल्म से अधिरित 2008 में आई इमरान हाशमी की फिल्म 'जनरल' को काफी पसंद किया गया था। फैंस अभी भी इस फिल्म को पसंद करते हैं और देखते हैं। ऐसे में फैंस 'जनरल' के भी सीक्ल का इंतजार कर रहे हैं। अब हाल ही में बात करते हुए इमरान हाशमी ने जनरल के सीक्ल को लेकर बड़ी जनकारी साझा की है। इमरान हाशमी ने बताया कि वो जनरल के सीक्ल पर विचार कर रहे हैं और इस पर काम भी किया जा रहा है।

**मजबूत स्क्रिप्ट मिले**  
पर ही बनेगी जनरल 2

सीक्ल पर काम करने की पूछी करने के बाद

अभिनेता ने कहा, टीम इसमें कोई जटिलाजी नहीं करना चाहती है और न ही इसे बर्बाद करना चाहती है। जब हमें लोगों कि हमारे पास एक मजबूत और उम्मीद स्क्रिप्ट है जो फिल्म की कहानी से आगे बढ़ती है, तब हम इस पर बढ़ते हैं। हम सिर्फ इसके लिए सीक्ल नहीं बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि कहानी भी बढ़ती है। तब हम इसके धोषणा करते हैं। हम चाहते हैं कि जनरल के सीक्ल पर विचार कर रहे हैं और इस पर काम भी किया जा रहा है।

**जुलाई में शुरू होगी**  
'आवारापन 2' की शूटिंग

कुछ दिनों पहले ही इमरान हाशमी ने 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' के सीक्ल 'आवारापन 2' की धोषणा की थी। अभिनेता ने बताया था कि फिल्म की शूटिंग जुलाई 2025 से शुरू होने वाली है। मौजूदा वर्क में रिकॉर्टिंग चल रही है और फिल्म 3 अप्रैल 2026 को रिलीज होने की संभावना है।

25 अप्रैल को रिलीज होनी 'ग्राउंड जीरो' इमरान हाशमी अपनी आगामी फिल्म 'ग्राउंड जीरो' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। एसल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्वित 'ग्राउंड जीरो' 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

कैसे निकले, ताकि हम और भी किरदारों पर ध्यान दे पाए और दूसरे ड्रॉमोशन को भी अच्छे से कर पाए। खुद को हील करना बहुत जरूरी है।

**सोशल मीडिया पर बनेगी फिल्म**

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के जुड़े मुश्किलों के बारे में बात करते हुए नुसरत ने कहा कि मैंने यह मानती हूं कि कुछ वर्षों में हम सोशल मीडिया पर फिल्म बना रहे होंगे और उसमें सोशल मुद्दा ही होगा सोशल मीडिया की ट्रोलिंग, क्योंकि हम तब तक इस बारे में अच्छे से समझ नुक्के होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत से लोग तात्पर में जा रहे हैं और जान भी ले रहे हैं। ये बहुत दावनी चीजें हैं।

**सोशल मीडिया पर बनेगी फिल्म**

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के जुड़े मुश्किलों के बारे में बात करते हुए नुसरत ने कहा कि मैंने यह मानती हूं कि कुछ वर्षों में हम सोशल मीडिया पर फिल्म बना रहे होंगे, क्योंकि हम तब तक इस बारे में अच्छे से समझ नुक्के होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत से लोग तात्पर में जा रहे हैं और जान भी ले रहे हैं। ये बहुत दावनी चीजें हैं।

**शाहरुख खान के साथ काम करेंगे अरशद वारसी**

सोशल मीडिया का जो प्रेरणा है, जो भयनक है। हम ऐसे नहीं जी सकते हैं। हम कुछ वर्क बाद ऐसी फिल्म बना रहे होंगे, जहा लोग सोशल मीडिया का प्रेरणा को दिखा रखे होंगे। इस पर फिल्म बनी तो यह आदत हो गई है कि हम लोगों को दिखा है। अब लोगों को नाम नहीं, उनके सोशल मीडिया हैं। हम बहुत डायरेक्टरों को जानते हैं। यह जाह बहुत डायरेक्टरों ही होती है। युधु तो प्रशान है, तो लेकिन बच्चों के लिए बहुत डरी हुई है, लेकिन इससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकत। परंतु बाजार जाना, सब्जी खरोदाना रोटी का काम था। अब हम अनिलाइन बैठकर घुसी रुकी हैं, तो मार्केट कौन जाएगा? हमें अपनी जिंदगी ऐसा बना ली है, इसलिए हमें ऐसी यही रहना होगा, हम पोछे नहीं जा सकते।

**अरशद वारसी हुए फिल्म में शामिल?**

अब खबर है कि फिल्म में एक और कलाकार की एंट्री हुई है। अब पीपिंग मून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, किंग की कार्यरत में अरशद वारसी भी शामिल हो गए हैं, कृष्ण तौर पर अभिनेता इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और उनके किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी हो।

**अरशद की फिल्म में शाहरुख खान ने किया था कैमियो**

2005 में शाहरुख खान ने अरशद की फिल्म कुछ मीठी हो जाए तो लेकिन दोनों ने एक साथ ऐसी कौई फिल्म नहीं की है जिसमें उन्होंने पूरी भूमिका निभाई हो।

**दीपिका भी हाँगों पर फिल्म का हिस्सा?**

कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में एक विस्तृत कैमियो के लिए चुना गया है। कृष्ण तौर पर, वह फिल्म में शाहरुख खान की मार्फत आनंद ने एक अपरिवार द्वारा देखने पर लोगों को अप्राप्यता के लिए चुना गया है।

**दीपिका भी हाँगों पर फिल्म का हिस्सा?**

कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में एक विस्तृत कैमियो के लिए चुना गया है। कृष्ण तौर पर, वह फिल्म में शाहरुख खान की मार्फत आनंद ने एक अपरिवार द्वारा देखने पर लोगों को अप्राप्यता के लिए चुना गया है।

**दीपिका भी हाँगों पर फिल्म का हिस्सा?**

कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में एक विस्तृत कैमियो के लिए चुना गया है। कृष्ण तौर पर, वह फिल्म में शाहरुख खान की मार्फत आनंद ने एक अपरिवार द्वारा देखने पर लोगों को अप्राप्यता के लिए चुना गया है।

**दीपिका भी हाँगों पर फिल्म का हिस्सा?**

कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में एक विस्तृत कैमियो के लिए चुना गया है। कृष्ण तौर पर, वह फिल्म में शाहरुख खान की मार्फत आनंद ने एक अपरिवार द्वारा देखने पर लोगों को अप्राप्यता के लिए चुना गया है।

**दीपिका भी हाँगों पर फिल्म का हिस्सा?**

कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में एक विस्तृत कैमियो के लिए चुना गया है। कृष्ण तौर पर, वह फिल्म में शाहरुख खान की मार्फत आनंद ने एक अपरिवार द्वारा देखने पर लोगों को अप्राप्यता के लिए चुना गया है।

**दीपिका भी हाँगों पर फिल्म का हिस्सा?**

कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में एक विस्तृत कैमियो के लिए चुना गया है। कृष्ण तौर पर, वह फिल्म में शाहरुख खान की मार्फत आनंद ने एक अपरिवार द्वारा देखने पर लोगों को अप्राप्यता के लिए चुना गया है।

**दीपिका भी हाँगों पर फिल्म का हिस्सा?**

कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में एक विस्तृत कैमियो के लिए चुना गया है। कृष्ण तौर पर, वह फिल्म में शाहरुख खान की मार्फत आनंद ने एक अपरिवार द्वारा देखने पर लोगों को अप्राप्यता के लिए चुना गया है।

**दीपिका भी हाँगों पर फिल्म का हिस्सा?**

कुछ दिनो